PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 15 ▸ Mumbai ▸ Friday, 15 May to 21 May 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

संक्षिप्त खबरें

नीट परीक्षा रद्द होने पर एक्शन में सरकार

नई दिल्ली: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा नीट-यूजी को रद्द किए जाने के बाद अब सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने के मुद्दे पर पहली उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस अहम बैठक में शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग का मुख्य मकसद यही था कि रद्द हुई परीक्षा को अब नए सिरे से कैसे कराया जाए ताकि आगे कोई भी गड़बड़ी न हो। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार 'री-नीट' पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन-रात मेहनत करने वाले छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो।

कोलकाता के डीसीपी पर एऊका शिकंजा

नई दिल्ली: कोलकाता से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को एक कथित वसूली रैकेट में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एक संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े मामले की जांच के दौरान की गई, जिसमें कुख्यात अपराधी सोना पप्पू और व्यवसायी जय कामदार के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और इसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है।

मंत्रियों की विमान यात्रा पर लगेगी सीएम की मंजूरी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रशासनिक खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब राज्य का कोई भी मंत्री, सीएम की पूर्व अनुमति के बिना चार्टर विमान या सरकारी विमान का उपयोग नहीं कर सकेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए मितव्ययिता के आह्वान के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं अत्यंत व्यस्त होने के कारण विमान का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए अब इस पर कड़ा नियंत्रण होगा। राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक के अधिक उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और किफायती बनाया जा सकता है। विमान उपयोग पर नियंत्रण और डिजिटल बैठकों को बढ़ावा देने जैसे फैसलों को सरकार वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

पांच देशों की यात्रा पर पीएम मोदी

यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी का खुद राष्ट्रपति बिन जायद ने किया स्वागत, आसमान में भेजे फाइटर जेट

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए यूएई के राष्ट्रपति

अबूधाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (15 मई) को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। इसके साथ ही उनके पांच देशों के महत्वपूर्ण विदेशी दौरे की शुरूआत हो गई है। 15 से 20 मई तक चलने वाले इस दौरे में यूएई के अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। शुक्रवार दोपहर जब पीएम मोदी का विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो यूएई की वायुसेना ने सम्मान और सुरक्षा के तौर पर उनके विमान को एस्कॉर्ट किया।

एफ-16 से किया स्वागत

प्रधानमंत्री के विमान से शूट किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही यूएई के एफ-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को सुरक्षा घेरा प्रदान करते हुए उनका शानदार स्वागत किया। अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया।

यूएई के बाद यूरोपीय देशों का दौरा

यूएई का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला यूरोप की ओर बढ़ेगा:

1. नीदरलैंड (15-17 मई) : पीएम मोदी डच प्रधानमंत्री रॉब जेतेन के साथ वार्ता करेंगे। इसके साथ ही उनकी मुलाकात राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी होगी।

मुख्य फोकस: दोनों देशों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, रक्षा और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे।

2. स्वीडन (17-18 मई) : स्वीडन में वह स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और स्वीडिश पीएम, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन के साथ मिलकर 'यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।

मुख्य फोकस: यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक), उभरती हुई तकनीकों, हरित ऊर्जा संक्रमण और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विशेष चर्चा होगी।

3. नॉर्वे (19 मई) : पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 'तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता भी भाग लेंगे। इसके अलावा, वह नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

4. इटली (19-20 मई) : अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी इटली पहुंचेंगे। वहां वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला के साथ वार्ता करेंगे।

मुख्य फोकस: भारत और इटली के बीच स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार बढ़ते सहयोग के बीच यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा देगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला

आपदा में मौत पर चार लाख रुपये की मिलेगी आर्थिक मदद

लखनऊ : प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पशुहानि, फसलों के नुकसान और खेतों से गाद हटाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह वर्षा सिंचित क्षेत्र में 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र

में 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 12 माही फसलों और कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा अतिवृष्टि के कारण खेतों में जमा गाद और मलबा हटाने के लिए भी 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता देने का प्रावधान किया है। इससे प्रभावित किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद मिलेगी। दुधारू पशुओं जैसे गाय-भैंस की मृत्यु पर 37,500 रुपये तक सहायता दी जाएगी। बैल और घोड़े जैसे गैर दुधारू पशुओं के लिए 32 हजार रुपये तथा बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू के लिए 20 हजार रुपये की सहायता तय की गई है। भेड़, बकरी और सुअर की क्षति पर भी 4 हजार रुपये प्रति पशु आर्थिक मदद दी जाएगी।

एनटीए ने नीट एग्जाम की नई तारीख का किया एलान

देशभर में 21 जून को होगी परीक्षा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नीट-यूजी की नई तारीख का एलान कर दिया है। अब यह परीक्षा देशभर में 21 जून को होगी। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। हालांकि, पेपर लीक की आशंका के चलते यह सवालों के घेरे में आ गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मई 2026 साइकिल में किए गए रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारिता और चुने गए परीक्षा केंद्रों को दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आगे भी मान्य रखा जाएगा। इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों द्वारा पहले से जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी।

बलूचिस्तान में कोहराम

विद्रोहियों के हमले में मेजर समेत 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर

नई दिल्ली : पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई ताजा मुठभेड़ों में एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कम से कम 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने पूरे प्रांत में सुनियोजित घात लगाकर ये हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चमालंग इलाके में पाकिस्तानी सेना जब एक 'इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन' चला रही थी, तभी बीएलए लड़ाकों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। इस भीषण गोलाबारी में मेजर तौसीफ और उनके साथ 10 अन्य सुरक्षाकर्मी मौके पर ही मारे गए। बीएलए ने इस हमले के लिए भौगोलिक स्थिति का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बरखान जिले में सात लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया

है। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच के अनुसार, सुराब जिले में सैन्य काफिले पर रॉकेट और ऑटोमैटिक हथियारों से किए गए हमले में दो गाड़ियां तबाह हो गईं और 10 सैनिक मारे गए। इसके अलावा, विद्रोहियों ने संचार और बिजली ढांचे को भी निशाना बनाया है। कोलवाह में एक कम्युनिकेशन टावर को आग के हवाले कर दिया गया, वहीं मस्तुंग में पुलिस गश्ती टीम को बंधक बनाकर हथियार छीन लिए गए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने नसीराबाद जिले के मीरवाह इलाके में विस्फोटक लगाकर दो बिजली ट्रांसमिशन टावरों को उड़ा दिया।

संपादकीय

विजय की तमिलनाडु चुनाव में प्रचंड विजय

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय ने वो कारनामा करके दिखाया जो अभी तक राजनीति में बहुत कम बार हुआ। उन्होंने नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम की स्थापना की और पहले ही चुनाव में बड़ी बढ़त बनाकर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए हैं और अभिनेता से एक बड़े राजनेता बनने वाले हैं। लाखों लोगों के मन में उनके बारे में कई सवाल हैं जिसमें से उनकी एजुकेशन को भी जानना चाहते हैं। लेकिन हम आपको उनके बारे में रोचक तथ्य बताते हैं। थलपति विजय कॉलेज ड्रॉपआउट स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग की फील्ड चुनने के दौरान अपनी पढ़ाई को अधूरा ही छोड़ दिया जो वे कभी पूरी नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई चेन्नई के स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया। लेकिन उनका मन पढ़ाई में न लगकर एक्टिंग में था जिसके चलते उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर पूर्ण रूप से एक्टिंग को अपना करियर बनाया और आज वे देशभर में सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। तमिलनाडु चुनाव में उतरने से पहले ही थलपति विजय ने अपने 33 साल के एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर राजनीति में उतर रहा हूं तो मुझे इस पर पूरा फोकस करना होगा। उनके इसी फोकस और डेडिकेशन ने उन्हें आज तमिलनाडु राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया है। विजय की जीत का असली राज उनके एक बड़े फैसले में छिपा है। राजनीति में आने वाले हजारों एक्टर फिल्मों के साथ-साथ सत्ता भी चाहते हैं। लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया, "अब फिल्में नहीं, सिर्फ जनसेवा मेरा लक्ष्य है।" फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कहने के उनके इस फैसले ने वोटर्स का दिल जीत लिया। लोगों में यह भरोसा जगा कि "ये आदमी सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया है।" दो नावों पर पैर रखने के बजाय, एक फुल-टाइम राजनेता के तौर पर जनता के सामने आना ही उनकी पहली जीत थी। सिर्फ 52 साल के विजय को तमिलनाडु के युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट मिला। अपने पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाया और कहा, "मैं आपके घर का सदस्य हूं, आपके परिवार के हर शख्स के लिए आया हूं।" उन्होंने जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर तमिल पहचान को सबसे ऊपर रखा। DMK और AIADMK की राजनीति से तंग आ चुकी जनता को विजय एक ताजे और भरोसेमंद 'तीसरे विकल्प' के तौर पर दिखे। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 49 वर्षों से केवल दो ही द्रविड़ पार्टियों, द्रमुक और अन्नाद्रमुक का दबदबा रहा। राज्य की सत्ता हमेशा इन्हीं दोनों खेमों के बीच घूमती रही है, लेकिन अब अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस दशकों पुराने एकाधिकार को सीधी और कड़ी चुनौती दी और 108 सीटों पर इनकी पार्टी ने जीत हासिल की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विजय की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही थी। वो वोट में परिवर्तित होती दिखी। 49 साल की मजबूत द्रविड़ सत्ता के सामने विजय एक बड़े तूफान की तरह खड़े हुए और विपक्षियों को हवा में उड़ा दिया।

...और सशक्त हो परमाणु आवरण

हाल में भारत के परमाणु कार्यक्रम ने एक मील का पत्थर तब पार किया, जब कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की। 'क्रिटिकलिटी' वह स्थिति है जब परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है। इस स्वदेशी तकनीक पर आधारित उपलब्धि के साथ ही भारत ने 1950 में होमी भाभा द्वारा तैयार किए गए त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा कर लिया, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितना परमाणु ईंधन खर्च करता है, उससे अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस चरण में बनने वाले यूरेनियम-233 को तीसरे चरण में थोरियम-232 के साथ उपयोग करने पर यह और अधिक यूरेनियम-233 बनाता है और अंततः इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए मात्र थोरियम की ही आवश्यकता रह जाती है। इसका महत्व इससे और बढ़ जाता है कि दुनिया भर में थोरियम का एक चौथाई भंडार भारत के पास है। इस परमाणु कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा होने पर भारत अगले अनेक दशकों तक थोरियम से ऊर्जा का उत्पादन करता रह सकता है। अभी व्यावसायिक उपयोग हेतु उर्जा उत्पादन के लिए रूस और भारत ही दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का संचालन कर रहे हैं। निःसंदेह कलपक्कम में प्राप्त हुई सफलता नागरिक उपयोग हेतु परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अप्रतिम उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े। हमने आज तक दो ही बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहली बार वर्ष मई 1974 में और अंतिम बार परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में किए थे। 1974 के परीक्षणों में मात्र एक डिवाइस का परीक्षण किया गया था, वहीं 1998 में परीक्षणों में पहले दिन तीन और फिर दो न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया गया। 1998 में पहले दिन परीक्षण की गई शक्ति-1 की क्षमता भारत के दावे के अनुसार 58 किलोटन रही थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का आकलन इसके लगभग 40 किलोटन रहने का था। अगर सरकार के दावे को भी सही मानें तो

यह इसलिए चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि चीन के पास 650 किलोटन से लेकर 3-4 मेगाटन के परमाणु हथियार हैं। चीन के हल्के परमाणु हथियार भी 150 किलोटन क्षमता के हैं। परीक्षण ही किसी वैज्ञानिक क्षमता को हासिल कर लेने का प्रमाण होता है। यही कारण है कि अमेरिका ने आज तक लगभग 1000 से अधिक, रूस ने 715 और चीन ने 45 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। इसके विपरीत भारत ने बेहद कम क्षमता के बस छह परमाणु परीक्षण ही किए हैं। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से परमाणु परीक्षण करने की बात कही थी। यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो फिर रूस भी पीछे नहीं रहने वाला। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। चीन पिछले कई वर्षों से गुपचुप तरीके से छोटे परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ है। 2024-25 में उसने परमाणु बम बनाए। मिसाइल प्रतिरोधक प्रणालियों की बढ़ती क्षमताओं और चीन के आबादी बहुल क्षेत्रों का भारतीय सीमा से बहुत दूर स्थित होने, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में हमसे कहीं आगे होने जैसे पहलुओं को देखते हुए भारत के लिए चीन के सापेक्ष भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का विस्तार आवश्यक है। ट्रंप के दौर में भारत को लेकर अमेरिका की नीतियों में आक्रामकता का पुट भी देखा जा सकता है। इसे देखते हुए भी हमें अपनी सामरिक तैयारी और मजबूत करनी होगी। यह न भूला जाए कि 2021 में लक्षद्वीप में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जोन पोल जोंस अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत के एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन में घुस आया था। बीते दिनों भी भारत से युद्धाभ्यास कर लौट रहे ईरानी नौसेना के जहाज को श्रीलंका के पास अमेरिकी नौसेना ने डुबो दिया था। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी शक्तियों को वैसे ही हवा दे रहा है, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने से पहले उसने रूस के पड़ोसी देशों में रूस के विरुद्ध दी थी। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी आक्रामकता से निपटने के लिए रूस ने भी स्मार्ट परमाणु हथियारों के विकास और परीक्षण का ही रास्ता चुना है। उसने परमाणु ऊर्जा से संचालित ब्यूरेवेस्टनिक नाइन एम 730 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो बेहद कम ऊंचाई जैसे मात्र 50 से 100 मीटर पर हफ्तों तक उड़ान भरती रही सकती है, क्योंकि इसके अंदर लगा बेहद छोटा परमाणु संयंत्र इसे बहुत लंबे समय तक ऊर्जा मुहैया कराता रहता है। असीमित ईंधन होने के चलते वह सीधे रास्ते के बजाय चक्कर काटकर या समुद्र के ऊपर से घूमकर किसी भी दिशा से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। मौजूदा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालियां उसे रोक नहीं सकतीं। अक्टूबर 2025 में किए गए परीक्षण में इस मिसाइल ने लगातार 15 घंटों तक उड़ान भरी और 14,000 किमी की दूरी तय की। रूस द्वारा विकसित पोसीडान को भी दुनिया का सबसे अनोखा और खतरनाक परमाणु हथियार माना जाता है। यह एक विशाल परमाणु-संचालित अंतरमहाद्वीपीय टारपीडो है। इसमें लगा छोटा परमाणु रिएक्टर इसे असीमित दूरी तक ले जाने की क्षमता देता है और यह हफ्तों तक एक किमी से अधिक की गहराई पर समुद्र में विचरण करता रह सकता है। इसके प्रहार से ऐसी सुनामी लहरें पैदा हो सकती हैं जो न्यूयार्क या लंदन सरीखे तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं और उस पूरे इलाके को दशकों के लिए रेडियोधर्मी प्रदूषण से अनुपयोगी बना सकती हैं। पोखरण परीक्षणों के तीन दशक बाद भारत के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि वह बदले हुए परिदृश्य को देखते हुए नए सिरे से परमाणु परीक्षण करे। इसके साथ ही मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालियों को चकमा देने वाले स्मार्ट परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों का विकास भी उतना ही आवश्यक है।

राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक समरसता, संस्कृति-संरक्षण एवं आपदा-प्रबंधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भारत का एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई। संगठन का घोषित उद्देश्य राष्ट्र-चेतना का जागरण, सामाजिक समरसता की स्थापना तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन है।

कार्य-पद्धति एवं सामाजिक प्रभाव : संघ अपनी दैनिक शाखाओं तथा विविध सेवा-प्रकल्पों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, चरित्र-निर्माण, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा-भाव के विकास पर बल देता है। शिक्षा, ग्राम-विकास, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे क्षेत्रों में संघ-प्रेरित अनेक संगठन एवं गतिविधियाँ देश के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं।

आपदा-प्रबंधन एवं सेवा-संवेदनशीलता : बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं महामारी जैसी आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकों की सेवा-गतिविधियाँ उल्लेखनीय रही हैं। राहत एवं बचाव कार्य, अन्न-वितरण, अस्थायी शिविरों का संचालन, चिकित्सा सहायता तथा पुनर्वास प्रयासों में संगठन की सहभागिता विभिन्न अवसरों पर देखने को मिली है।

विमर्श के विविध पक्ष : समर्थकों के अनुसार यह संगठन राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक चेतना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं, आलोचकों द्वारा इसकी वैचारिक दिशा एवं सार्वजनिक-राजनीतिक प्रभाव पर विभिन्न प्रश्न भी उठाए जाते रहे हैं। इन विविध दृष्टिकोणों के बावजूद, भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में इसकी भूमिका एक निरंतर विमर्श का विषय बनी हुई है।

स्कूलों में दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट खत्म हों

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर दें ध्यान : आशीष सूद

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि स्कूलों में दुर्घटना की आशंका वाले कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए। स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के आसपास ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चिंता जताने के साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद मंगलवार को शिक्षा निदेशालय की ओर से सूरजमल विहार स्थित सीएम श्री स्कूल में (ईस्ट जोन-1 एवं जोन-2) में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों से रूबरू थे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आईएनए से कड़कड़डूमा कोर्ट तक दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। इसके बाद मेट्रो स्टेशन से सीएम श्री स्कूल ई-रिक्शा से पहुंचे। संवाद में मंत्री आशीष सूद ने शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, स्कूल संसाधन, स्वच्छता, सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने का भी आग्रह किया। माना-बीएलओ ड्यूटी व अन्य कामों में शिक्षकों को लगाने से पढ़ाई प्रभावित होती है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र के दौरान आयोजित होते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकार अब इस दिशा में विचार कर रही है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से गर्मी की छुट्टियों में आयोजित किया जाए तथा उनका शेडयूल पहले से जारी किया जाए ताकि शिक्षक अपनी योजनाएं उसी अनुरूप बना सके।

प्यूपिल्स टाइम्स

अंबरनाथ चुनाव परिणाम के बाद सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से भेंट

अंबरनाथ : अंबरनाथ के राजनीतिक परिणाम के बाद आज कल्याण के कार्यसम्राट सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से शिष्टाचार भेंट की गई।

इस मौके पर बदलापुर शहर अध्यक्ष वामनशेठ म्हात्रे, अंबरनाथ शहर अध्यक्ष सदा मामा पाटील, नगरसेवक सचिन पाटील, नगरसेविका पूनम शेलार, सुनीता पाटील तथा नवनिर्वाचित स्वीकृत नगरसेविका अश्विनी पाटील उपस्थित रहीं। बैठक में अंबरनाथ की राजनीतिक स्थिति और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद महोदय ने एकजुट होकर काम करने का मार्गदर्शन दिया।

अंबरनाथ: युति प्रस्ताव पर शिवसेना में मतभेद

वरिष्ठ नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा

अंबरनाथ: अंबरनाथ नगरपालिका में भाजपा के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को लेकर शिवसेना में विभिन्न मत सामने आए हैं। सोमवार को पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने शहर के विकास हेतु भाजपा से युति का प्रस्ताव पत्रकार वार्ता में रखा।

इस पर वरिष्ठ नगरसेवक राजेंद्र वाळेकर ने कहा कि पार्टी के 27 निर्वाचित नगरसेवकों से चर्चा किए बिना प्रस्ताव रखना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युति के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय सभी को मान्य होगा, परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है।

फिलहाल जिला स्तरीय नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया है। सभी नगरसेवकों की संयुक्त बैठक के बाद ही वरिष्ठ नेतृत्व को सुझाव भेजा जाएगा। पार्टी का कहना है कि संगठनात्मक एकता और अंबरनाथ का विकास ही प्राथमिकता है।

महाराष्ट्र ने पुराने वाहनों के लिए

HSRP की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटलगाने की डेडलाइन 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे लाखों गाड़ी मालिकों को इस जरूरी सिक्योरिटी उपाय को मानने के लिए और समय मिल जाएगा। यह फैसला तब आया जब राज्य ने पूरे महाराष्ट्र में HSRP लगाने की रफ़्तार का रिव्यू किया और पाया कि बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियों ने अभी तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है। इससे पहले, इसे मानने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 तय की गई थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह बढ़ाने का मकसद गाड़ी मालिकों को होने वाली परेशानी से बचाना है और सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू करना पक्का करना है।

महाराष्ट्र बोर्ड ने जून-जुलाई 2026 के लिए SSC सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन शुरू किए

मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने जून और जुलाई 2026 में होने वाली ररउ सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक, स्टूडेंट्स 15 मई से 22 मई तक बिना लेट फीस के ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। 23 मई से 25 मई के बीच जमा की गई एप्लीकेशन पर लेट फीस लगेगी। यह प्रोसेस संबंधित स्कूलों और ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन के जरिए किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री लिखित परीक्षाएं 16 जून, 2026 से शुरू होंगी, जबकि थ्योरी परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल और ओरल परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित होने की उम्मीद है। बोर्ड जल्द ही डिटेल्ड टाइमटेबल और हॉल टिकट शेड्यूल जारी करेगा। ये परीक्षाएं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फरवरी-मार्च 2026 की ररउ बोर्ड परीक्षाओं में एक या ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो मार्क्स में सुधार चाहते हैं। बोर्ड ने कहा कि सप्लीमेंट्री परीक्षाएं स्टूडेंट्स को एकेडमिक साल गंवाए बिना सब्जेक्ट क्लियर करने का मौका देती हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बोर्ड पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय स्टूडेंट की डिटेल्स ध्यान से वेरिफाई करें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यह भी सलाह दी गई है कि वे एग्जाम शेड्यूल और प्रोसेस के बारे में MSBSHSE द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें।

मुंबई में जाम की टेंशन खत्म... कोस्टल रोड से जुड़ेंगे ये 10 बड़े रूट

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि पीक ऑवर्स में चंद किलोमीटर का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है. इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए बीएमसी ने वसोर्वा-दहिसर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के उत्तरी हिस्से को शहर के कई प्रमुख मार्गों से जोड़ने का निर्णय लिया है. इस कनेक्टिविटी योजना का मुख्य उद्देश्य कोस्टल रोड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर होने वाले संभावित जाम को रोकना है. वर्तमान में मुंबई के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से या मध्य मुंबई की ओर जाने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH), लिंक रोड और एसवी रोड ही मुख्य विकल्प हैं. इन सड़कों पर वाहनों की संख्या उनकी क्षमता से कई गुना अधिक है. वसोर्वा-दहिसर कोस्टल रोड को एक वैकल्पिक ह्यनॉर्थ-साउथ कॉरिडोरह्ल के रूप में विकसित किया जा रहा है. बीएमसी के इंजीनियरों का मानना है कि यदि कोस्टल रोड को सीधे तौर पर शहर की आंतरिक मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया, तो कोस्टल रोड से उतरते ही जंक्शनों पर भारी जाम लग जाएगा. इसी ह्यबॉटलनेकह्ल समस्या को खत्म करने के लिए 10 फीडर रोड्स और कनेक्टिंग रूट्स को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है. बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पहले की योजनाओं में सीमित इंटरचेंज पॉइंट्स थे, लेकिन अब रणनीति बदल दी गई है. अब वाहनों को केवल एक या दो मुख्य इंटरचेंज पर निर्भर नहीं रहना होगा. कोस्टल रोड पर जगह-जगह एंट्री और एग्जिट की सुविधा दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव अलग-अलग इलाकों में बंट जाएगा. इससे पश्चिमी उपनगरों के भीतर की गलियों और मुख्य चौराहों पर वाहनों की कतारें कम होंगी. इस योजना का सबसे अहम हिस्सा जेवीपीडी (जुहू-विलेपार्ले विकास योजना) फ्लायओवर

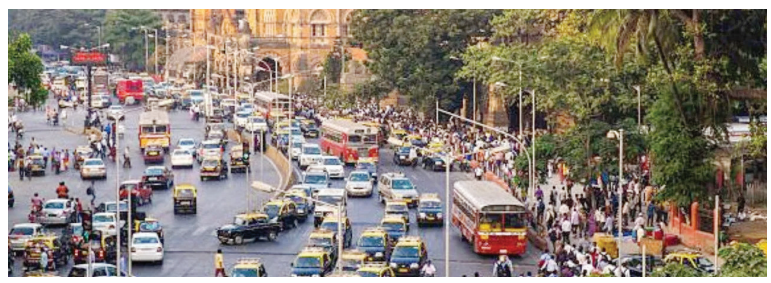

का जुड़ाव है. इस फ्लायओवर को वसोर्वा लिंक रोड से जोड़ा जाएगा, जो आगे चलकर वसोर्वा-बांद्रा सी लिंक कनेक्टर के माध्यम से सीधे कोस्टल रोड में मिल जाएगा. इसके पूरा होने पर गोखले ब्रिज से आने वाले वाहन सीडी बर्फीवाला फ्लायओवर का उपयोग करते हुए सीधे कोस्टल रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकेंगे. वहीं, लोखंडवाला और वसोर्वा-माध ब्रिज को भी कोस्टल रोड से जोड़ने की योजना है. लोखंडवाला के पास माध इंटरचेंज के जरिए एक नया रास्ता खुलेगा, जो वाहनों को सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर ले जाएगा. इसके साथ ही एमएमआरडीए जोगेश्वरी-वसोर्वा लिंक रोड के विस्तार पर भी काम कर रही है, जो इस पूरे नेटवर्क को और मजबूती देगा. बीएमसी ने मलाड से लेकर दहिसर तक के सफर को सुगम बनाने के लिए माइंडस्पेस, चारकोप और गोराई जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को इंटरचेंज के जरिए कनेक्ट करने का प्लान बनाया है. कोस्टल रोड के साथ-साथ बीएमसी एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है- 5.5 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर. यह मगाठाणे और गोरेगांव के बीच बनेगा और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के समानांतर चलेगा. यह कॉरिडोर कोस्टल रोड को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (ऋटछफ) से जोड़ेगा. इससे मुंबई की ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आएगा और यात्रियों को प्रस्तावित ट्विन टनल (जुड़वां सुरंग) तक सीधी पहुंच मिलेगी.

रामचंद्र नाला ब्रिज लिंक: मलाड के इस आगामी ब्रिज को माइंडस्पेस इंटरचेंज के जरिए जोड़ा जाएगा.

चारकोप सेक्टर-8: इस इंटरचेंज को पोइसर जंक्शन के पास एसवी रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे लिंक रोड और एसवी रोड के बीच का ट्रैफिक सुगम होगा.

दहिसर कनेक्टर: गोराई इंटरचेंज और कांदरपाड़ा रोटरी को भी कोस्टल रोड नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा.

प्यूपिल्स टाइम्स

सीएम फडणवीस ने लॉन्च किया नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2027 का आधिकारिक लोगो

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेले के आधिकारिक लोगो को आज लॉन्च किया। इसका अनावरण सह्याद्री अतिथीगृह में आयोजित समारोह में सीएम फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभमेले के लोगो के चयन के लिए कुंभमेला प्राधिकरण की ओर से देशव्यापी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से 3 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयनित तीन विजेताओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुणे के सुमित काटे को तीन लाख रुपये का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। वहीं नोएडा के मयंक नायक को द्वितीय स्थान के लिए दो लाख रुपये तथा पंढरपुर के पीयूष पिंपलनेरकर को तृतीय स्थान के लिए एक लाख रुपये और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लोगो चयन प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध डिजाइन विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी, जिसमें प्रसून जोशी, अश्विनी देशपांडे, मंदार राणे, वृषाली केकणे (देशमुख), बारिश दाते, विनय नारंग, डॉ. प्राजक्ता बास्ते, प्रफुल सावंत, डॉ. दिनेश वैद्य, एथनी लोपेझ और डॉ. किरण शिंदे शामिल थे। समिति ने सर्जनशीलता, नवाचार, ब्रांड सुसंगतता और प्रस्तुतीकरण जैसे मानकों के आधार पर लोगो का चयन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति के सदस्यों का भी सम्मान किया। कुंभमेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने प्रस्तावना के दौरान कुंभमेले की तैयारियों और लोगो प्रतियोगिता की जानकारी दी। कार्यक्रम में कुंभमेला मंत्री गिरीश महाजन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नासिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेला प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह सहित विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों ने उपस्थित संत-महात्माओं का स्वागत किया।

नासिक सिंहस्थ कुंभ के लोगो की विशेषताएं

>> लोगो नासिक और त्र्यंबकेश्वर की पवित्र धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है।

>> भगवान शिव का त्रिशूल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक दशार्या गया है।

>> त्र्यंबकेश्वर मंदिर की आकृति क्षेत्रीय धार्मिक धरोहर को दशार्ती है।

कालाराम मंदिर की कमान और गोदावरी नदी को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

>> गोदावरी नदी को ह्यशिवलिंगह्न के स्वरूप में दशार्ते हुए कुंभमेले की पवित्र स्नान परंपरा के महत्व को रेखांकित किया गया है।

मुंबई में जलभराव रोकने के लिए बीएमसी का विशेष अभियान

31 मई तक पूरी होगी नालों की सफाई

मुंबई : आगामी मानसून को देखते हुए बीएमसी ने नालों और नदियों की सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि नालों से निकाली गई गाद 48 घंटे के भीतर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाकर उसका निपटान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुंबई के बड़े और छोटे नालों की सफाई तथा गाद निकालने का कार्य 31 मई तक हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ तेजी से काम करना होगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर वहां प्रभावी उपाय किए जाएं।

चलाएं विशेष अभियान

>> उप अभियंता और सहायक अभियंता को प्रतिदिन कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। बांगर ने तैरते कचरे यानी फ्लोटिंग मटेरियल को हटाने के लिए मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

>> उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले नालों और ड्रेनेज पाइपलाइन की पूरी सफाई सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मुंबईकरों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।

गर्मियों में मतदाता सूची SIR प्रक्रिया टालने की मांग

बीएमसी आयुक्त ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

मुंबई : बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया गर्मी के महीनों में शुरू न की जाए, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में मुंबईकर छुट्टियों के लिए शहर से बाहर रहते हैं। यह कदम राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। अश्विनी भिड़े ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में जो मांगें सामने आईं, उन्हें आयोग तक पहुंचा दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में चल रहे जनगणना कार्य के कारण फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया कराना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों कार्यों में एक ही कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जनगणना के पहले चरण के तहत घरों की सूची तैयार करने का कार्य 16 जून तक चलेगा। वर्तमान में राज्य में प्री-एसआईआर मैपिंग का काम जारी है, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची के नामों का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। हालांकि, राज्य निर्वाचन कार्यालय को अब तक एसआईआर लागू करने के संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

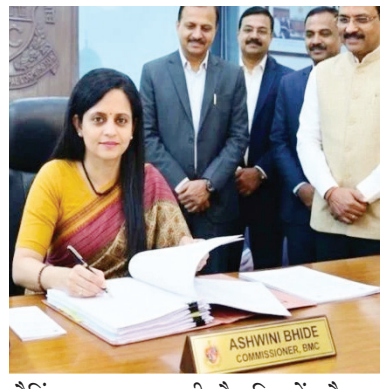

6 चरणों में लागू होगा एसआईआर कार्यक्रम

उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो वर्षों तक कोई चुनाव निर्धारित नहीं है, इसलिए एसआईआर को जल्दबाजी में कराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस। चोक्कालिंगम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की थी।

पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2002 में यह प्रक्रिया पूरी होने में 13 महीने लगे थे। एसआईआर कार्यक्रम छह चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमे प्री-रिवीजन मैपिंग, गणना, एएएसडी सूची (पहले से पंजीकृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची) तैयार करना, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करना, दावे और आपत्तियां लेना तथा अंतिम सूची प्रकाशित करना शामिल है।

मुंबई में दिखने लगा गर्मी का असर

हरी सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर

मुंबई : बढ़ती भीषण गर्मी का असर अब सीधे आम आदमी के किचन पर पड़ रहा है। गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम होने से एपीएमसी बाजार में आवक कम हो गई है और मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। रिटेल मार्केट में हरी बीन्स के दाम 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बाजार में प्रतिदिन करीब 400 गाड़ियों से 1970 टन सब्जियों की आवक हो रही है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी का असर यह दिख रहा है कि मांग के मुकाबले सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। गर्मी के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए व्यापारियों को भी एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर सतारा, पुणे और सांगली इलाकों से आने वाली हरी बीन्स का उत्पादन कम होने से इसके दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। थोक बाजार में हरी बीन्स का दाम जहां 160 से 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वहीं रिटेल मार्केट में यह 200 से 250 रुपये में बिक रहा है।

कंट्रोल में टमाटर, पत्ता गोभी के दाम

>> ग्वार और घेवर भी 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और मटर और टोंडली के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। इस बीच, धनिया के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहा है। एपीएमसी में 20 से 26 रुपये प्रति किलो मिलने वाली धनिया रिटेल मार्केट में 45 से 50 रुपये में बिक रही है।

>> टमाटर और पत्ता गोभी के दाम अभी भी कंट्रोल में होने से कंज्यूमर्स को कुछ राहत मिली है। मार्केट कमेटी में पत्ता गोभी का दाम जहां 4 से 6 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वहीं रिटेल मार्केट में यह 40 से 60 रुपये में बिक रहा है। थोक बाजार में टमाटर का भाव 12 से 24 रुपये है, जबकि खुदरा बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा ऐलान

27 गांवों की पानी समस्या खत्म करने के लिए 100 करोड़ मंजूर

■ गौरव सिंह प्यूपिल्स टाईम्स संवाददाता

कल्याण: कल्याण-डोंबिवली में स्वास्थ्य, पानी और आधारभूत सुविधाओं को लेकर बड़े स्तर पर विकास योजनाओं की शुरूआत होने जा रही है। कल्याण लोकसभा सांसद डॉ। श्रीकांत शिंदे ने बुधवार को केडीएमसी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए। सबसे अहम घोषणा कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल और डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल को 500-500 बेड के अत्याधुनिक सुपर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में विकसित करने की रही। इसके साथ ही दोनों अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। बैठक में सांसद शिंदे ने 27 गांवों की जल समस्या को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। इसमें 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 50 करोड़ रुपये केडीएमसी खर्च करेगी। नई जलवाहिनियां बिछाने, पानी की टंकियां बनाने और पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने का काम अगले कुछ महीनों में तेज किया जाएगा। सांसद शिंदे ने दावा किया कि अगले 10 महीनों में 27 गांवों की पानी समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उच्च रक्तचाप का प्रबंधन

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

उच्च रक्तचाप (Hypertetesion) आज की जीवनशैली से जुड़ा गंभीर रोग है, जिसे आधुनिक चिकित्सा 'साइलेंट किलर' मानती है। आयुर्वेद में इसे मुख्यतः 'रक्तगत वात'तथा 'शिरोगत वात' के रूप में समझा गया है। इसके मूल कारणों में अत्यधिक नमक, तला-भुना भोजन, तनाव, क्रोध, अनिद्रा, व्यायाम की कमी तथा वात-पित्त दोष का असंतुलन शामिल हैं।

आयुर्वेद केवल रक्तचाप की संख्या नहीं देखता, बल्कि शरीर और मन दोनों के असंतुलन को रोग का आधार मानता है। सर्पगंधा, अर्जुन छाल, ब्राह्मी, जटामांसी और लहसुन जैसी औषधियाँ रक्तचाप नियंत्रण में सहायक मानी जाती हैं। अर्जुन हृदय को बल देता है, जबकि ब्राह्मी और जटामांसी मानसिक तनाव कम करती हैं। आहार-विहार में लौकी, जौ, मूंग, अनार तथा हल्का भोजन लाभकारी माना गया है। अधिक नमक, चाय-कॉफी, शराब और अचार से परहेज आवश्यक है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और तिल तेल से अभ्यंग उपयोगी बताए गए हैं।

योग और प्राणायाम—विशेषतः अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, शीतली तथा योग निद्रा—मानसिक तनाव घटाकर रक्तचाप संतुलित करने में सहायक हैं।

आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग दबाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और जीवनशैली में संतुलन स्थापित करना है। फिर भी गंभीर उच्च रक्तचाप में आधुनिक चिकित्सा की सलाह अनिवार्य है।

रेल पटरियों पर नई क्रांति

क्या वंदे भारत स्लीपर बदल देगी लंबी दूरी की यात्रा?

भारतीय रेलवे आधुनिकता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भविष्य की प्रीमियम लंबी दूरी सेवा माना जा रहा है। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावित गति, आधुनिक डिजाइन और उन्नत सुविधाओं के साथ यह ट्रेन पारंपरिक राजधानी एक्सप्रेस मॉडल को नई चुनौती दे सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का उद्देश्य केवल तेज यात्रा नहीं, बल्कि अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तकनीक-आधारित अनुभव प्रदान करना है। इनमें आधुनिक स्लीपर कोच, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, कम कंपन और शोर, स्वचालित दरवाजे, उन्नत सुरक्षा प्रणाली तथा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई आंतरिक संरचना शामिल है। रेलवे के लिए यह परियोजना भारतीय रेल नेटवर्क के व्यापक आधुनिकीकरण का प्रतीक मानी जा रही है। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो यात्रा समय घटेगा, प्रीमियम रेल सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और भारतीय रेलवे की वैश्विक छवि भी मजबूत होगी। हालाँकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल आधुनिक ट्रेन पर्याप्त नहीं है। उच्च गति के अनुरूप ट्रैक, सिग्नलिंग, समयबद्ध संचालन और सुरक्षा ढाँचे को भी समान रूप से मजबूत करना होगा। आने वाले वर्षों में वंदे भारत स्लीपर वास्तव में भारतीय रेल यात्रा की परिभाषा बदल सकती है।

मितव्ययिता, सोना और आर्थिक अनुशासन का संदेश

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता अपील को केवल नैतिक संदेश नहीं, बल्कि आर्थिक सतर्कता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संकट का सीधा प्रभाव महँगाई, परिवहन लागत और आम नागरिक के घरेलू बजट पर पड़ता है।

प्रधानमंत्री ने ईंधन बचत, अनावश्यक खर्च में कमी, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपभोग पर जोर दिया है। इसके साथ ही सीमित एवं संतुलित गोल्ड खरीदारी की अपील भी आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण आयातक देशों में शामिल है और अत्यधिक सोना आयात होने से विदेशी मुद्रा भंडार तथा व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda द्वारा इस अपील का समर्थन किए जाने को आर्थिक मुद्दों पर उभरती राष्ट्रीय सहमति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तेल और सोने का आयात समान रूप से बढ़ता रहा, तो महँगाई और चालू खाता घाटा दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का संकेत यह भी है कि नागरिक केवल पारंपरिक स्वर्ण निवेश तक सीमित न रहें, बल्कि बैंकिंग, उद्योग, स्टार्टअप और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को भी बढ़ावा दें। ऐसे समय में आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिक अनुशासन और जिम्मेदार उपभोग से भी तय होगी।

सम्मान और संवेदना की रेल

वरिष्ठ नागरिक रियायत बहाली का समय

कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराया रियायत अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। उस समय आर्थिक दबाव और आपात परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक माना गया। किंतु अब जब देश सामान्य परिस्थितियों की ओर लौट चुका है, तब इस सुविधा की बहाली की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है।

देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा उपचार, धार्मिक यात्राओं, पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक कारणों से नियमित रेल यात्रा करते हैं। सीमित पेंशन और बढ़ती महँगाई के बीच पूर्ण किराया वहन करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसे में रेलवे रियायत केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक भी है। भारतीय रेलवे आज वंदे भारत जैसी आधुनिक सेवाओं और तकनीकी विस्तार के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानवीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रेलवे चरणबद्ध तरीके से रियायत पुनः लागू कर सकती है—जैसे केवल स्लीपर और सामान्य श्रेणी में सीमित छूट, आयु आधारित प्राथमिकता या वार्षिक यात्रा सीमा जैसी व्यवस्थाएँ अपनाई जा सकती हैं। इससे रेलवे पर अत्यधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और बुजुर्गों को राहत भी मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। वृद्धावस्था में सम्मानजनक और सुलभ यात्रा सुविधा देना केवल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी है।

NEET प्रश्नपत्र का प्रकटन: प्रतिभा के मंदिर में सेंध

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-NEET-केवल एक प्रतियोगिता नहीं, अपितु भारत के भावी चिकित्सकों की तपोभूमि है। जब इस पावन तपोभूमि की प्राचीर में प्रश्नपत्र प्रकटन की सेंध लगती है, तो यह मात्र पत्रों का लीक होना नहीं है; यह करोड़ों युवाओं की आशा, अथक परिश्रम और राष्ट्र की स्वास्थ्य-व्यवस्था की आधारशिला पर किया गया निर्मम प्रहार है।

आहत कौन होता है?

वह विद्यार्थी, जिसने तीन वर्ष तक माता-पिता से विलग रहकर, प्रत्येक रजनी में NCERT को वेदवाक्य मानकर आराधना की। उसके श्रम-सीकरों का मूल्य उस क्षण निष्फल हो जाता है जब परीक्षा से पूर्व ही प्रश्नपत्र करोड़ों में क्रय-विक्रय का विषय बन जाए। यह दृश्य परिश्रमी युवा के अंतःकरण को विदीर्ण कर देता है और 'सत्यमेव जयते' के उदात्त उद्घोष को कलंकित करता है। यह केवल परीक्षा नहीं, तंत्र का दिवाला है प्रश्नपत्र का प्रकटन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की दक्षता, शासन की संकल्पशक्ति और समग्र मूल्यांकन-प्रक्रिया की पवित्रता पर गंभीर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। जब अर्थबल प्रतिभा पर विजय प्राप्त करने लगे, तो सुदूर ग्राम का वह मेधावी कहाँ जाए जिसके लिए शिक्षण-शुल्क जुटाना भी दुर्गम हो? यह असमानता सामाजिक न्याय का गला घोंट देती है।

अब रुदन नहीं, संधान चाहिए

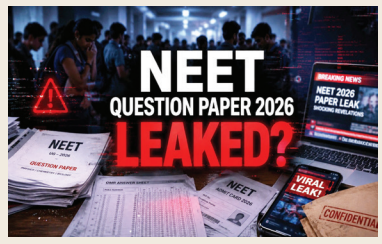

जाँच-समितियाँ गठित करना निदान नहीं, समग्र तंत्र का आमूल रूपांतरण अपरिहार्य है:

1. प्रौद्योगिकीय दुर्भेद्यता: प्रश्नपत्र का निर्माण, मुद्रण, परिवहन प्रत्येक सोपान बहुस्तरीय कूटलेखन, खंडशृंखला-सत्यापन और सजीव भू-स्थान निगरानी के अधीन हो।

2. दंड की कठोरता: प्रकटन के षड्यंत्र में संलिप्त प्रत्येक अपराधी झ मध्यस्थ, अधिकारी अथवा परीक्षार्थी के लिए दस वर्ष का सश्रम कारावास, संपत्ति अधिहरण तथा सार्वजनिक सेवा से आजीवन निष्कासन का विधान हो।

3. शीघ्र न्याय: प्रश्नपत्र प्रकटन सिद्ध होते ही 72 घंटे के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्परीक्षा की स्वचालित प्रणाली प्रवर्तित की जाए।

4. नैतिक संरक्षण: प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर संचार-अवरोधक, कृत्रिम मेधा आधारित मुख-सत्यापन, जैवमितीय प्रवेश एवं वायवीय निगरानी को अनिवार्य मानक बनाया जाए।

राष्ट्र का आह्वान

ठएएळ भारत के आरोग्यमय भविष्य की आधारशिला है। यदि यह आधारशिला ही शिक्षा-माफिया के कुटिल आघातों से चूर-चूर हो जाएगी, तो 'स्वस्थ भारत' का संकल्प कैसे फलीभूत होगा?

परीक्षाओं की निष्कलुषता केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, यह भारतवासियों का सामूहिक धर्म-संग्राम है। जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम अभ्यर्थी को न्यायपूर्ण मंच उपलब्ध नहीं होता, तब तक 'विकसित भारत' का स्वप्न अधूरा ही रहेगा।

स्मरण रहे- जिस राष्ट्र में प्रतिभा का तिरस्कार होता है, वहाँ उन्नति पंगु हो जाती है। अब समय है कि हम प्रकटन नहीं, प्रतिज्ञा करें - न्याय की, निष्पक्षता की, नवोन्मेषी भारत की।

जेबे विज्ञानम, मनसि जिज्ञासा

पॉकेट-साइन्स इत्यस्य वास्तविक : मूलमन्त्रः

अद्यतनः कालः विज्ञानस्य कालः अस्ति। प्रातःकाले चलदूरभाषस्य घोषेण उत्थानात आरभ्य रात्रौ अन्तजार्ले सञ्चरणं कृत्वा निद्रां यावत, अस्माकं सम्पूर्णं जीवनं विज्ञानेन परिवेष्टितम अस्ति। स्मार्ट-दूरभाषः, ऑनलाइन-भुगतानम, मौसमपूवार्नुमानम, वैक्सीन, कृत्रिमबुद्धिमत्ता च—एते सर्वे विज्ञानस्य एव देन्यः सन्ति।

तथापि एकः विरोधाभासः स्पष्टतया दृश्यते—वयं विज्ञानस्य उपयोगं कुर्मः, किन्तु तस्य ज्ञातुं जिज्ञासा शनैः शनैः न्यूनता गच्छति। वयं जीपीएस इत्यस्य साहाय्येन मार्गं प्राप्नुमः, किन्तु उपग्रहाः अस्माकं स्थानं कथं निर्धारयन्ति इति न चिन्तयामः। विद्युत्स्विचं सञ्चालयामः,

परन्तु ऊर्जा अस्माकं गृहम कथं प्राप्नोति इति न पृच्छामः। एतादृशे समये 'पॉकेट-साइन्स' इत्यस्य अवधारणा अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा भवति। अस्य अर्थः अस्ति—तादृशं विज्ञानं यत सरलम, व्यावहारिकम, दैनन्दिनजीवनेन सह सम्बद्धं च भवेत। अस्य मूलमन्त्रः अस्ति— 'प्रत्येकं प्रश्नं महत्त्वपूर्णं मन्यध्वम, जिज्ञासां च जीवितां धारयध्वम।' वास्तविकं विज्ञानं केवलं प्रयोगशालासु न वर्तते, अपितु अस्माकं परितः अपि दृश्यते। जलस्य उष्णतायां पात्रस्य आवरणं कुतः कम्पते? इन्द्रधनुः कथं निर्मीयते? वनस्पतयः सूर्यस्य दिशि कुतः नमन्ति? एते लघुप्रश्नाः एव महान वैज्ञानिकचिन्तनस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति। विज्ञानं सर्वदा जिज्ञासायाः एव जन्म लभते। अत्र विद्यालयानां भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। विद्यालयाः केवलं पाठ्यपुस्तकपठनपर्यन्तं सीमिताः न भवेयुः, अपितु प्रश्नपृच्छनस्य संस्कृतिं विकसितुं प्रयत्नं कुर्युः। लघुप्रयोगाः, क्रियात्मकशिक्षणम, 'अद्यतनः प्रश्नः' इत्यादयः प्रयासाः बालकेषु वैज्ञानिकदृष्टिकोणं विकसितुं शक्नुवन्ति। भारतस्य सदृशे देशे पॉकेट-साइन्स केवलं शिक्षायाः विषयः न, अपितु सामाजिकावश्यकता अपि अस्ति। अन्धविश्वासानां अफवाहानां च अस्मिन युगे वैज्ञानिकचेतना एव समाजं तर्कस्य प्रमाणस्य च मार्गे नेतुं शक्नोति। भविष्यं तेषामेव समाजानां भविष्यति, येषां जेबेषु केवलं चलदूरभाषः न, अपितु विज्ञानं जिज्ञासा च अपि भविष्यतः। यतः विज्ञानस्य महानतमं साधनं काचित यन्त्रणा न, अपितु प्रश्नं पृच्छन मनः अस्ति।

यदा दुःखं केवलं 'कण्टेण्ट्' भवति

डिजिटल-भारते मन्दीभूतसं वेदनानाम आत्मचिन्तनम

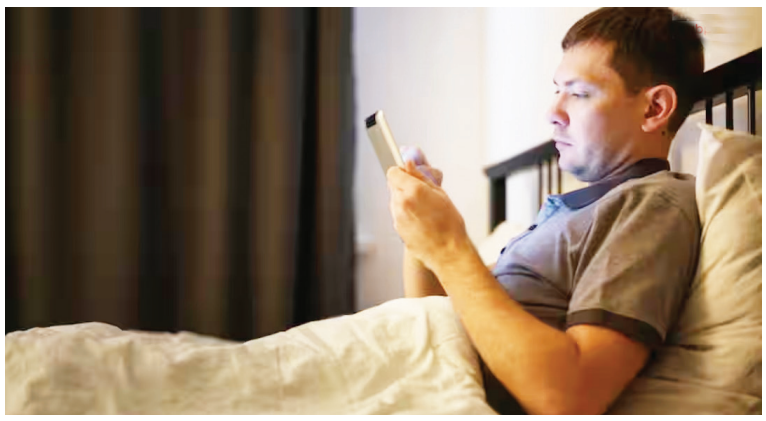

रात्रेः द्वौ वादनौ एकादश निमेषाश्च। मुम्बई-नगर्यां वर्षा निवृत्ता आसीत, किन्तु वातायनात अद्यापि जल-बिन्दवः पतन्ति स्म। कक्षे केवलं दूरभाषस्य नीलप्रकाशः आसीत। अद्वैतः पार्श्वं परिवर्त्य पुनः दूरभाषम उद्घाटितवान। तस्य अङ्गुल्यः अधुना निरन्तर-स्क्रोलिङ्गे अभ्यस्ताः अभवन। प्रथमं दृश्यं सीमायां वीरगतिं प्राप्तस्य सैनिकस्य अन्त्ययात्रायाः आसीत। द्वितीयं मार्गे जातायाः हिंसायाः निगूढचित्रग्रहणयन्त्रेण गृहीतं दृश्यं आसीत। तृतीयं च—एकः वातार्पाठकः उच्चैः वदति स्म— 'देशे नियमस्य भयम समाप्तं किम?' अद्वैतः किंचित अस्मितवान, किन्तु ततः स्वस्यैव हास्येन अस्वस्थः अभवत। बाल्यकाले यदा दूरदर्शने हिंसासम्बद्धाः वार्ताः आगच्छन्ति स्म, तदा तस्य माता तत्क्षणमेव दूरदर्शनं निरोद्धुम् उक्तवती— 'बालकैः एतादृशं न द्रष्टव्यम।' अधुना स एव बालकः प्रतिरात्रं युद्धं, हिंसां, क्रन्दनं, द्वेषं च पश्यति, ततः कतिपय-निमेषानन्तरं शान्तः निद्रां गच्छति। तदैव तेन अनुभूतम—समस्या केवलं हिंसा नास्ति। वास्तविकसमस्या एषा अस्ति यत हिंसा अधुना अस्माकम अन्तःकरणं न स्पृशति। अधुना दुःखम अनुभूतिः न, अपितु 'कण्टेण्ट्' इव जातम। जनाः घटनाः न अनुभवन्ति, केवलम अङ्गुलिभिः सञ्चालयन्ति। अद्वैतः पुनः सामाजिकमाध्यमम उद्घाटितवान। विश्वविद्यालये जातायाः हिंसायाः वार्ता प्रसारिता आसीत। अधः सहस्रशः प्रतिक्रियाः दृश्यन्ते स्म। केचन उपहासं कुर्वन्ति स्म, केचन तस्य समर्थनं कुर्वन्ति स्म। अतीव अल्पाः एव अवदन-'एतद् अमानुषम।' तस्मै अनुभूतम-अधुना जनाः हिंसायाः विषये वक्तुं पूर्वं पृच्छन्ति-'अयं स्वकीयः उत परकीयः?' दूरभाषं निरुध्य सः चिरकालं छदम अपश्यत। बहिः पुनः वर्षा आरब्धा आसीत। तस्मै अकस्माद् अनुभूतम-सभ्यतां रक्षितुं सर्वदा वक्तुमेव आवश्यकं नास्ति; कदाचित विरम्य अनुभवनम अधिकम आवश्यकम। यतः यस्मिन दिने अपरिचितस्य दुःखम अस्मान स्प्रष्टुं न शक्नुयात, तस्मिन दिने समाजः केवलं जनसमूहः भविष्यति। कक्षे निस्तब्धता आसीत। बहुकालानन्तरं च अद्वैतः एकां करुणध्वनिम अश्रृणोत-स्वस्य अन्तःकरणे। सम्भवतः तस्य नाम एव तम आह्वयति स्म।

स्वर्णस्य दश महाराजान

यदा विश्वे युद्धानि, आर्थिक-अस्थिरता, प्रतिबन्धाः च वर्धन्ते, तदा राष्ट्राणि स्वर्णे अधिकं विश्वासं कुर्वन्ति। मई २०२६ समयेटी अमेरिका ८,१३३ टन स्वर्णेन सह विश्वस्य सर्वाधिकं स्वर्ण-भण्डारं धारयति। तस्य अनन्तरं जर्मनी, इटली, फ्रान्स, रूस, चीन च प्रमुख-स्थानानि धारयन्ति। रूस तथा चीन गतवर्षेषु तीव्रतया स्वर्ण-क्रयं कृतवन्तौ, यतः तौ डॉलर-निर्भरता न्यूनकर्तुम इच्छतः। स्विट्जरलैण्ड् लघु-राष्ट्रम अस्ति, तथापि विशाल-स्वर्ण-भण्डारेण वित्तीय-विश्वासस्य प्रतीकं मन्यते। भारतः अपि ८२२ टन स्वर्णेन विश्वस्य प्रमुख-स्वर्ण-भण्डार-राष्ट्रेषु गणनीयः अस्ति। भारतीय-रिजर्व-बैङ्कः निरन्तरं स्वर्णं क्रिणाति। किन्तु भारतस्य वास्तविकं सामर्थ्यं भारतीय-गृहेषु निहितम अस्ति। अनुमानतः भारतीय-परिवाराणां समीपे २५,००० टन अधिकं स्वर्णं विद्यते, यत विश्वस्य महत्तमं घरेलु-स्वर्ण-भण्डारं मन्यते। अद्य स्वर्णं केवलं भूषणं न, अपितु आर्थिक-सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य, आत्मविश्वासस्य च प्रतीकम अस्ति। यदा विश्वं कम्पते, तदा राष्ट्राणि स्वर्णे एव विश्वासं स्थापयन्ति।

पञ्च-मिनट-कार्यकारी-सारांश

'वैश्विक-अस्थिरता विरुद्ध आर्थिक-अनुशासनम'

१. कूटनीतिः – भारतस्य सन्तुलन-नीतिः- प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पञ्च-राष्ट्र-भ्रमणम : वअए, नीदरलैण्ड्, स्वीडन, नॉर्वे, इटली च। मुख्य-विषयाः — ऊर्जा-सुरक्षा, हरित-हाइड्रोजन, अर्धचालक-सम्झौताश्च। BRICS-विदेशमन्त्री-सभा, नवी-दिल्ली (१४-१५ मई) : ईरान-इजरायल-संघर्षः मुख्यः विषयः भविष्यति। भारतस्य अमेरिका-रूस-खाडी-देशानां मध्ये सन्तुलनं स्थापनीयम। प्रभावः : तैल-आपूर्तेः संरक्षणम तथा पाश्चात्य-देशैः सह प्रौद्योगिकी-सहकार्यस्य सुदृढीकरणम।

२. अर्थव्यवस्था- होर्मुजतः गृह-व्ययपर्यन्तम तैल-संकटम : होर्मुज-क्षेत्रे तनाववृद्ध्या कच्च-तैलस्य मूल्यं $९० अतिक्रमितुं शक्नोति। तेन पेट्रोल-डीजल-मूल्यवृद्धिः, यातायात-व्ययवृद्धिः, खाद्य-मूल्यवृद्धेः च सम्भावना। RBI निरीक्षणमः २१ मई दिने MPC-प्रतिवेदनम प्रकाशितं भविष्यति। यदि मुद्रास्फीति-दरः ५% अतिक्रामति, तर्हि रेपो-दरे कठोर-नीतेः संकेताः दृश्येरन। अवसंरचना-विमर्शः : अहमदाबाद-ढोलेरा-अर्ध-उच्चगति-रेल-परियोजनानन्तरं बुलेट-रेल-जालस्य विषये राष्ट्रव्यापी चर्चा तीव्रा भविष्यति।

३. राजनीति- राज्येषु चलनशीलता केरल-राज्यम : मुख्यमन्त्री-चयन-विषये कांग्रेस-दले मन्थनम। महाराष्ट्रम : मराठा-आरक्षणं तथा मुम्बई-अवसंरचना-परियोजनाः राजनीतिक-विवादस्य केन्द्रं भविष्यन्ति। पश्चिमबङ्गः तथा तमिलनाडुः : निर्वाचनानन्तरं विपक्षीय-संघटनस्य नूतन-समीकरणानि चचार्यां भविष्यन्ति।

४. न्यायपालिका- चत्वारः प्रमुख-विवादाः उच्चतम-न्यायालयः : आरक्षण-नीतिः, डिजिटल-गोपनीयता,निर्वाचन-बॉण्ड-पारदर्शिता, सामाजिक-माध्यम-तथा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-नियमन-विषयेषु महत्त्वपूर्ण-श्रवणम। उच्च-न्यायालयाः : भूम्यधिग्रहणम, धार्मिक-स्थल-विवादाः, NEET-CUET-परीक्षा-विषयाः, नगरीय-अतिक्रमणम इत्यादयः।

५. समाजः तथा धर्मः- मार्गतः सञ्चार-माध्यमपर्यन्तम १६ मई : शनिजयन्ती तथा वट-सावित्री-व्रतम। देवालयेषु, घाटेषु च विशाल-जनसमागमः सम्भाव्यः। यातायात-व्यवस्थापनं चुनौतीरूपेण भविष्यति। डिजिटल-विमर्शः : AI-दीपफेक, मिथ्या-सूचनाः, युवानां मानसिक-स्वास्थ्यं च सरकारस्य न्यायालयस्य च विशेष-दृष्टौ भविष्यन्ति

६. अन्तर्राष्ट्रीय-परिदृश्यम- त्रिषु मोचार्सु तनावः पश्चिम-एशिया : ईरानझ इजरायल-संघर्षेण तैल-बाजारः तथा अंश-बाजारः अस्थिरः भवितुमर्हति। रूसझयूक्रेन-संघर्षः : यूरोपे रक्षा-व्यय-वृद्धेः विषये चर्चा वर्धिष्यते। अमेरिकाझचीन-स्पर्धाः अर्धचालक-तथा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-विषये नूतन-प्रतिबन्धाः अथवा वक्तव्याः सम्भाव्याः। सारांशः-त्रिंशत-सेकेण्डेषु अस्मिन सप्ताहे भारतं चतस्रः प्रमुखाः चुनौतयः एकस्मिन समये समालोचयितुं बाध्यत-

१. कूटनीतिः - विश्वस्य सन्तुलन-रक्षणम।

२. ऊर्जा- तैल-मूल्यवृद्धेः नियन्त्रणम।

३. अर्थव्यवस्था- विकासस्य मुद्रास्फीतेः च मध्ये सन्तुलनम।

४. समाजः - उत्सव, न्यायालय-विमर्शः, डिजिटल-चर्चाः च सम्यक नियोजयितुम। जोखिमम यदि तैलस्य मूल्यं $१०० अतिक्रामति, तर्हि मुद्रास्फीति तथा निर्वाचन-राजनीतिः उभे अपि उग्ररूपं धारयेताम। अवसरः BRICS-सहयोगः तथा यूरोप-भ्रमणम निवेश-प्रौद्योगिकी-

डॉ. वंदना मिश्रा

सहकार्यस्य नूतन-द्वाराणि उद्घाटयितुं शक्नोति। अन्तिम-वाक्यम् अयं सप्ताहः निर्णेष्यति यत भारतं 'अस्थिरतायामपि अनुशासनम' इति आदर्शं स्थापयितुं समर्थं भविष्यति वा न वा।

TAVI / TAVR : A Modern Revolution in Heart Valve Replacement Without Opening the Chest

Dr. Arvind singh Rana

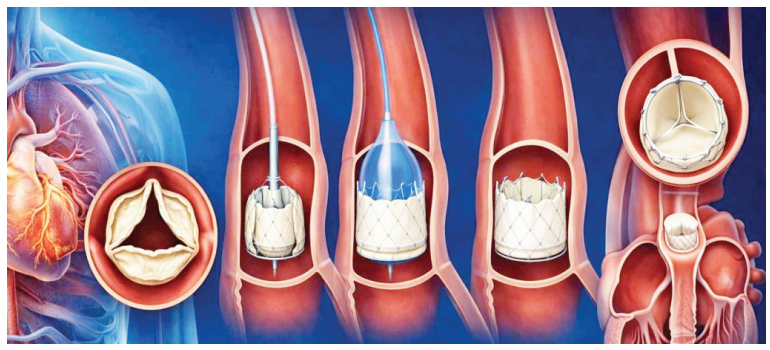

Among the most significant advances in cardiovascular medicine over the past decade, TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), also known as TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement), holds a special place. This modern procedure allows doctors to replace a narrowed aortic valve without performing open-heart surgery. The chest does not need to be opened, and the heart usually does not need to be stopped during the procedure.

In TAVI, a small 5–6 mm puncture is made in the artery of the groin, through which a catheter carrying a biological artificial valve is guided to the heart. The new valve is implanted inside the diseased valve itself. The procedure generally takes 60–120 minutes. Most patients are able to walk the next day and return home within 3–4 days. TAVI has emerged as a life-saving option particularly for elderly patients or those considered high-risk for conventional open-heart surgery. Patients with weak lungs, kidney disease, prior bypass surgery, stroke history, or advanced age often benefit greatly from this technique. Symptoms of severe aortic stenosis include breathlessness, chest pain, dizziness, and fainting. Without timely treatment, the condition can become fatal.

The major advantages of TAVI include the absence of a large surgical incision, no requirement for a heart-lung machine, reduced blood loss, faster recovery, and the possibility of treatment even in very elderly patients. However, certain limitations remain. The valve durability is generally estimated at 10–15 years, some patients may require a permanent pacemaker, and the overall cost of the procedure is still relatively high.

Since 2018, TAVI technology has expanded rapidly in India. Today, many advanced cardiac centers across the country offer this procedure, and the development of "Make in India" valves has helped reduce treatment costs.

TAVI has transformed the treatment landscape for elderly patients with severe aortic valve disease. Nevertheless, proper patient selection, an experienced heart team, and timely diagnosis remain the true keys to successful outcomes.

Rangasamy Scripts History

Sworn in as Puducherry CM for Record 5th Term

Pupils Times Reporter

N. Rangasamy took oath as the Chief Minister of Puducherry on Wednesday, 13 May 2026. This is his 5th term, a record for the highest number of times any leader has become Chief Minister in the history of the Union Territory.

Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy to Rangasamy at Lok Bhavan. President Droupadi Murmu had appointed him as Chief Minister on 9 May 2026.

Along with the Chief Minister, two MLAs were sworn in as ministers. BJP MLA A. Namassivayam and AINRC MLA Malladi Krishna Rao were inducted into the Cabinet.

In the Assembly election results declared on 4 May, the NDA secured a majority by winning 18 seats in the 30-member Assembly. In the alliance, AINRC won 12, BJP won 4, AIADMK won 1, and LJK won 1 seat.

76-year-old Rangasamy registered victories from both Thattanchavady and Mangalam Assembly constituencies. He has previously served as Chief Minister from 2001-2006 and 2006-2008 with Congress, and from 2011-2016 and 2021-2026 under the leadership of AINRC.After taking oath, Rangasamy said that the government will implement all public welfare schemes effectively and Puducherry will be developed on the lines of Singapore. The next Cabinet expansion is expected to take place soon.

"CBSE Result 2026: From Grade Inflation to Governance-Based Evaluation Reform"

The CBSE Class 12 Result 2026 records a pass percentage of 85.20%, marking a significant recalibration in recent academic outcomes. This is among the lower levels observed since 2019 (83.40%), indicating that the unusually high pass rates of the COVID-19 period (2020–2022), driven by liberal evaluation policies, are now steadily normalizing.

It is also observed that the number of candidates rose from approximately 11.92 lakh in 2020 to 17.68 lakh in 2026, reflecting a substantial increase of nearly 48.3%. Despite this expansion in participation, the decline in pass percentage signals a shift toward a more standardized and comparatively rigorous evaluation framework.It is further established that around 98.66 lakh answer scripts were evaluated through the On-Screen Marking (OSM) system. This confirms the full-scale institutionalization of digital assessment, which enhances transparency, strengthens inter-evaluator consistency, and reduces manual error in the examination process.

It is clearly noted that the system has actively controlled grade inflation. Students scoring above 95% remain below 1%, while those above 90% account for approximately 13%. This indicates a deliberate shift toward a more normalized and statistically balanced score distribution.

It is also recorded that approximately 1.63 lakh students have been placed in the compartment category, representing about 9.26% of total candidates. This highlights concerns related to academic preparedness and learning outcomes, while the supplementary examination framework continues under NEP 2020's "no year loss" policy design.

Institutional performance gaps remain evident, with Kendriya Vidyalayas at 98.55% and Navodaya Vidyalayas at 98.47%, compared to 84.22% in private schools. This reflects the influence of institutional structure, teacher quality, and academic discipline on student outcomes. In conclusion, the CBSE Class 12 Result 2026 reflects a clear transition from grade inflation toward a governance-driven, competency-based, and digitally regulated evaluation ecosystem, with long-term implications for higher education admissions and national GER dynamics.

PUPILS TIMES

Friday, 15 May to 21 May 2026

Sacred exposition of Holy Buddha Relics concludes in Ladakh

Draws over 1.18 lakh devotees

The 14-day Sacred Exposition of the Holy Relics of Tathāgata Buddha concluded in Ladakh on Thursday, with more than 1.18 lakh devotees from across India and abroad paying obeisance during one of the largest spiritual gatherings ever organised in the Union Territory. The closing ceremony was held at the Dharma Centre in Choglamsar, Leh, and was attended by Ladakh Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena. The concluding event coincided with the annual Monlam Chenmo, or Great Prayer Festival of Ladakh, dedicated to world peace and universal happiness. Thousands of monks, nuns, Rinpoches and devotees participated in the prayers and traditional sacred mask dances known as Chhams. The Holy Relics were inaugurated for public exposition on May 1 on the occasion of the 2569th Buddha Purnima by Union Home Minister Amit Shah at Jivetsal in Leh. Addressing the gathering, Saxena said the exposition symbolised cultural harmony and spiritual unity, adding that Ladakh was emerging as a global destination for peace and spiritual awakening. "The sacred relics of Lord Buddha will return tomorrow to the National Museum in Delhi, but their blessings will remain here forever. Let us together establish Ladakh at the global level as a centre of peace, contemplation and spiritual awakening," he said. The Lieutenant Governor also praised the people of Ladakh for maintaining discipline and patience while standing in long queues for hours to seek blessings from the relics. The exposition witnessed participation from several dignitaries, including Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, Union Minister Kiren Rijiju, ambassadors of Sri Lanka and Thailand, Buddhist leaders, scholars and international pilgrims. Thousands of residents dressed in traditional attire had lined the roads from Leh Airport to Jivetsal on April 29 to welcome the relics upon their arrival in Leh. After remaining on public display in Leh for nine days, the Holy Relics were taken to Karsha Gonpa in Zanskar on May 11 and 12. Special prayers, cultural programmes, conferences and spiritual activities were organised throughout the exposition. His Eminence Drukpa Thuksey Rinpoche expressed gratitude to the Government of India, the Ladakh administration and participating organisations for successfully organising the event.

Self-Reliance, Jointness Essential For Strategic Autonomy : Rajnath Singh

New Delhi: Defence Minister Rajnath Singh on Thursday stressed the importance of self-reliance and jointness in securing India's strategic autonomy and preparing the country for future security challenges.Addressing the 'Kalam & Kavach 3.0' defence strategic dialogue through a video message at the Manekshaw Centre in New Delhi, the Defence Minister said national strength would increasingly depend on how effectively the armed forces, research laboratories and defence industries work together. "A nation's strength will increasingly depend on how quickly its defence forces, laboratories and industries think and act as one," he said. Rajnath Singh said future battlefields would reward nations capable of reducing the time between innovation, prototype development and operational deployment. He noted that evolving geopolitical tensions, cyber threats, supply-chain disruptions and hybrid warfare have made preparedness, resilience and innovation essential for national security. The Defence Minister described self-reliance in defence manufacturing as both an economic and strategic necessity, stating that excessive dependence on foreign suppliers for critical defence capabilities leaves nations vulnerable during crises. "We must design, develop, produce, maintain and upgrade key systems within our own national ecosystem. That is how we will secure our strategic autonomy," he said.

India Pushes Telecom Leadership At ITU Council Meet, Eyes Hosting Rights For PP-2030

New Delhi : India strengthened its position in the global telecommunications and digital policy landscape during the International Telecommunication Union (ITU) Council 2026 meeting held in Geneva, Switzerland, from April 28 to May 8. An Indian delegation led by Mukesh Kumar, Deputy Director General (International Relations), Department of Telecommunications (DoT), actively participated in key discussions related to global telecom governance and digital cooperation. During the meeting, India presented its proposal to host the ITU Plenipotentiary Conference (PP-2030), one of the organisation's most significant global conferences. According to the DoT, the ITU Council accepted India's proposal, marking a major milestone in the country's expanding role in shaping international telecom and digital policy discourse. The proposal is expected to receive final approval at the ITU Plenipotentiary Conference 2026 scheduled to be held in Doha, Qatar, in November this year. The Indian delegation, along with the Permanent Representative of India to the United Nations office in Geneva, also made interventions on several important issues including ITU regional presence, ITU membership, and the organisation of ITU events. As part of its campaign for upcoming ITU elections, India hosted a networking reception at the ITU premises on April 30, 2026, which saw participation from representatives of 69 member states. During the event, India presented its candidature for re-election to the ITU Council and for the post of Director, Radiocommunication Bureau (BR).

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS Printing Press,** UNIT NO.04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E) , MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)

Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**